



शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में विभिन्न महिला उद्यमियों में सशक्तिकरण भागफल के कारकों का आकलन

Monika Samaddar, Research Scholar, Department of Education,

Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University

Dr. Kuldeep Singh Tomar, Assistant Professor, Department of Education,

Maharaja Agrasen Himalayan Garhwal University

सारांश

माइक्रोफाइनेंस समाज के गरीब और कमजोर समूह को ऋण और संबद्ध वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने का प्रावधान है। वित्तीय क्षेत्र में इन समूहों को बहिष्कृत आबादी के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस प्रकार, समाज की बहिष्कृत आबादी को वित्तीय ऋण और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करने की आवश्यकता है। देश में अधिकतम परिवारों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार वित्तीय समावेशन के केंद्रित नीति उद्देश्य के साथ आई है। भारत सरकार (जीओआई) द्वारा 2008 में नियुक्त रंगराजन समिति ने वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण को विस्तृत किया और वित्तीय समावेशन के लिए एक कार्यशील परिभाषा प्रदान की। समिति के अनुसार, वित्तीय समावेशन को कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों जैसे कमजोर समूहों द्वारा वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाओं और समय पर और पर्याप्त ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गरीबों और कमजोर समूहों की सेवा करने के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणालियों की सीमाओं और सूचना स्रोतों से वित्त की सूदखोरी की शर्तों ने औपचारिक वित्त के समानांतर स्रोत के लिए नवाचार को जन्म दिया। मार्गुराइट एस. रॉबिन्सन द्वारा दी गई सूक्ष्म वित्त की विस्तृत परिभाषाओं में से एक में सूक्ष्म वित्त को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, 'सूक्ष्म वित्त से तात्पर्य ऋण और जमा दोनों के लिए लघु पैमाने की वित्तीय सेवाओं से है – जो उन लोगों को प्रदान की जाती हैं जो खेती करते हैं, मछली पकड़ते हैं या पशुपालन करते हैं; छोटे या सूक्ष्म उद्यम चलाते हैं जहां वस्तुओं का उत्पादन, पुनर्चक्रण, मरम्मत या व्यापार किया जाता है; सेवाएं प्रदान करते हैं; मजदूरी या कमीशन के लिए काम करते हैं; थोड़ी मात्रा में भूमि, वाहन, पशु या मशीनरी और औजारों को किराये पर देकर आय प्राप्त करते हैं; और विकासशील देशों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अन्य व्यक्तियों और स्थानीय समूहों को प्रदान की जाती हैं।

मुख्य शब्द: कार्यशील, पशुपालन, समावेशन, व्यापार, ग्रामीण, शहरी

1. परिचय

क्षेत्रीय समस्या और यह किसी एक क्षेत्र में फिट नहीं बैठता। इसलिए, गरीबी को दूर करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण के बजाय एक अभिनव दृष्टिकोण समय की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2000 में सहस्राब्दि विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं और इनमें से एक लक्ष्य 2015 तक गरीबी और भूख से पीड़ित लोगों के अनुपात को आधा करना है। इस संदर्भ में, माइक्रोफाइनेंस गरीबी में कमी और महिला सशक्तिकरण उपकरण के रूप में उभर रहा है।

भारत में, माइक्रोफाइनेंस की अवधारणा को नब्बे के दशक में नाबार्ड द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के निचले स्तरों में धन की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए पेश किया गया था। इसका उद्देश्य माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के साथ एसएचजी के जुड़ाव के माध्यम से ग्रामीण और शहरी गरीबी को खत्म करना है।

माइक्रोफाइनेंस समाज के गरीब और कमजोर समूह को ऋण और संबद्ध वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने का प्रावधान है। वित्तीय क्षेत्र में इन समूहों को बहिष्कृत आबादी के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस प्रकार, समाज की बहिष्कृत आबादी को वित्तीय ऋण और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करने की आवश्यकता है। देश में अधिकतम परिवारों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार वित्तीय समावेशन के केंद्रित नीति उद्देश्य के साथ आई है। भारत सरकार (जीओआई) द्वारा 2008 में नियुक्त रंगराजन समिति ने वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण को विस्तृत किया और वित्तीय समावेशन के लिए एक कार्यशील परिभाषा प्रदान की। समिति के अनुसार, वित्तीय समावेशन को कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों जैसे कमजोर समूहों द्वारा वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाओं और समय पर और पर्याप्त ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। गरीबों और कमजोर समूहों की सेवा करने के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणालियों की सीमाओं और सूचना स्रोतों से वित्त की सूदखोरी की शर्तों ने औपचारिक वित्त के समानांतर स्रोत के लिए नवाचार को जन्म दिया। मार्गुराइट एस. रॉबिन्सन द्वारा दी गई सूक्ष्म वित्त की विस्तृत परिभाषाओं में से एक में सूक्ष्म वित्त को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, 'सूक्ष्म वित्त से तात्पर्य ऋण और जमा दोनों के लिए लघु पैमाने की वित्तीय सेवाओं से है – जो उन लोगों को प्रदान की जाती हैं जो खेती करते हैं, मछली पकड़ते हैं या पशुपालन करते हैं; छोटे या सूक्ष्म उद्यम चलाते हैं जहां वस्तुओं का उत्पादन, पुनर्चक्रण, मरम्मत या व्यापार किया जाता है; सेवाएं प्रदान करते हैं; मजदूरी या कमीशन के लिए काम करते हैं; थोड़ी मात्रा में भूमि, वाहन, पशु या मशीनरी और औजारों को किराये पर देकर आय प्राप्त करते हैं; और विकासशील देशों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अन्य व्यक्तियों और स्थानीय समूहों को प्रदान की जाती हैं।

दूसरी ओर, नाबार्ड ने माइक्रोफाइनेंस को इस प्रकार परिभाषित किया है, "ग्रामीण, अर्ध-शहरी या शहरी क्षेत्रों में गरीबों को बहुत छोटी राशि में बचत, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं और उत्पाद उपलब्ध कराना, ताकि वे अपनी आय का स्तर बढ़ा सकें और जीवन स्तर में सुधार कर सकें।"

1.1 अध्ययन की आवश्यकता

उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आज एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जहां महिलाएं अपने व्यक्तिगत विकास पर स्वतंत्र निर्णय लेने के साथ-साथ समाज में समान रूप से चमक सकें। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट (सितंबर 2015) की नवीनतम रिपोर्ट दर्शाती है कि महिलाओं की समानता पर ध्यान केंद्रित करने से जोड़ सकते हैं

वैश्विक विकास के लिए +12 ट्रिलियन। सामाजिक, मानवीय, वित्तीय और बौद्धिक पहलुओं में महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करेगा कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक हासिल किया जाएगा, जिसमें लैंगिक समानता, आर्थिक स्थिरता, वित्तीय साक्षरता और महिलाओं के वित्तीय समावेशन पर कार्यक्रम शामिल हैं।

2. अध्ययन का उद्देश्य

1. शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में विभिन्न महिला उद्यमियों में सशक्तिकरण भागफल के कारकों का आकलन करना।
2. नीचे उल्लिखित कारकों के आधार पर शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए मॉडल विकसित करना।

3. साहित्य की समीक्षा

भाग्य जीबी (2020) में महिला उद्यमियों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की चुनौतियों के बारे में उल्लेख किया गया है, जिनके पास बहुत कम या मध्यम शिक्षा है जो उन्हें प्रतिस्पर्धी दुनिया में चुनौती के साथ पीछे छोड़ देती है। व्यापार में महिलाओं की स्वीकृति शहरी जनता द्वारा स्वीकार की जाती है और अभी तक ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुंचती है। माना जा रहा है कि महिलाएं परिवार से जुड़ी होती हैं और घर में बच्चे का पालन-पोषण करती हैं। एक उद्यमी होने के लाभों के बारे में बताना उसकी स्थिति को बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। लेखक महिलाओं के कौशल को प्रशिक्षित और तेज करने के लिए लोगों की समिति बनाने की सिफारिश करता है।

मोहम्मद जहीरुल हक, मोहम्मद अजीजुर रहमान और सुल्ताना रज़ियाहवे, (2019) ने बांग्लादेश में महिला उद्यमिता के बारे में बताया है, महिला उद्यमी, जिन्होंने जीवन की चुनौतियों को स्वीकार किया है और सामाजिक-आर्थिक विकास में नेताओं के रूप में उभरी हैं, के लिए कमाई करती हैं स्वयं और अपने परिवारों के लिए या महिलाओं के सामाजिक-राजनीतिक उत्थान में योगदान करने के लिए। लेखक ने इस्लामी कानून और पुरुषों और महिलाओं दोनों की समानता पर इसकी व्याख्या के बारे में उल्लेख किया है। बांग्लादेश में महिलाएं अब पहले की तुलना में अपने सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो गई हैं। समग्र रूप से, वे अब अर्थव्यवस्था के विकास, रोजगार के अवसरों के सृजन और देश की उत्पादकता में वृद्धि में बहुत योगदान दे रहे हैं।

किरण। आर. राव (2019) ने ग्रामीण महिला उद्यमियों का एक SWOT विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि वित्तीय संस्थान महिलाओं की उद्यमशीलता क्षमताओं के बारे में संशय में हैं। यह अध्ययन किया गया है कि ग्रामीण महिला उद्यमियों या उद्यमिता के विकास के लिए सामाजिक ग्रामीण वातावरण अनुकूल नहीं है। मॉल संस्कृति का विकास ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए सबसे बड़ी बाधा है।

परमशिवैया आर, राम्या। एस.के (2019) ने उल्लेख किया कि महिला सशक्तिकरण और वित्तीय आत्म-दक्षता उद्यमशीलता गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इस दिशा में कई एनजीओ महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। बहुत सी महिलाओं ने व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है और विश्व स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त की है। आम तौर पर, शहरी क्षेत्रों में महिलाएं कम से कम छोटे पैमाने पर व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न रही हैं। जैसा कि ग्रामीण के शहरीकरण की अवधारणा दिन का क्रम है, सरकार सकल मार्ग स्तर पर विकास के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रही है, और साथ ही, ग्रामीण महिलाओं को व्यवसाय या स्व-रोजगार गतिविधियों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं धीरे-धीरे आगे आ रही हैं। ऐसे उद्यम शुरू करना जिनके माध्यम से उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर के स्तर में वृद्धि हुई है, कई मामलों में इसकी सफलता के कारण, ग्रामीण उद्यमिता लोकप्रियता प्राप्त कर रही है। हालांकि महिला उद्यमियों को सफलता की कहानियों से प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन इसमें बाधाओं के उदाहरण हैं। इसलिए, ग्रामीण महिला उद्यमिता के लिए ट्रिगर और बाधाओं का अध्ययन एक चिंता का विषय है।

4. शोध पद्धति

1. प्राथमिक डेटा संग्रह प्रश्नावली, अनुसूचियों और व्यक्तिगत साक्षात्कारों के माध्यम से किया गया है।

2. द्वितीयक डेटा संग्रह पुस्तकों, पत्रिकाओं, अभिलेखों, पत्रिकाओं, वेब-साइटों और इसी तरह के माध्यम से किया गया है।

नमूना आकार: 500

अध्ययन में भारत के विभिन्न राज्यों से संबंधित 500 महिलाओं को शामिल किया गया है।

भारत की कुल जनसंख्या लगभग 1.21 बिलियन है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 833 मिलियन और शहरी जनसंख्या 377 मिलियन है। ग्रामीण महिलाओं की संख्या लगभग 410 मिलियन और शहरी महिलाओं की संख्या लगभग 180 मिलियन है। चूंकि ग्रामीण महिलाएं कुल शहरी महिलाओं की आबादी का आधे से अधिक हिस्सा हैं, इसलिए ग्रामीण और शहरी महिलाओं को दर्शाने के लिए 3:1 का अनुमानित अनुपात माना गया है। इस प्रकार, 380 कृषि महिलाओं और 120 शैक्षिक महिलाओं को नमूना आकार के रूप में चुना गया है। महिलाओं का चयन भारत के प्रमुख राज्यों से किया गया है और राज्यों को चार क्षेत्रों अर्थात् उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में विभाजित किया गया है। अध्ययन के अंतर्गत भारत के प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया है।

5. डेटा विश्लेषण और व्याख्या

तालिका 5.1 आयु समूह के लिए आवृत्ति

		आवृत्ति	प्रतिशत	वैध प्रतिशत	संचयी प्रतिशत
वैध	19 – 35 वर्ष	29	24.2	24.2	24.2
	36 से 60 वर्ष	84	70.0	70.0	94.2
	60 वर्ष से अधिक	7	5.8	5.8	100.0
	कुल	120	100.0	100.0	

- 19 – 35 वर्ष आयु वर्ग के लिए आवृत्ति 29 है और प्रतिशत 24.2 है
- 36 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लिए आवृत्ति 84 है और प्रतिशत 70 है
- 60 से अधिक वर्ष आयु वर्ग के लिए आवृत्ति 7 है और प्रतिशत 5.8 है

- आयु वर्ग के लिए कुल आवृत्ति 120 है और प्रतिशत 100 है
- व्याख्या: उपरोक्त तालिका और ग्राफ से, यह अनुमान लगाया गया है कि शैक्षिक क्षेत्र से साक्षात्कार की गई अधिकांश महिलाएँ 36 से 60 वर्ष की आयु की थीं।

तालिका 5.2: शैक्षणिक योग्यता की आवृत्ति

		आवृत्ति	प्रतिशत	वैध प्रतिशत	संचयी प्रतिशत
वैध	स्नातक	31	25.8	25.8	25.8
	स्नातकोत्तर और उससे ऊपर	86	71.7	71.7	97.5
	डिप्लोमा	2	1.7	1.7	99.2
	अन्य	1	.8	.8	100.0
	कुल	120	100.0	100.0	

- स्नातक में शिक्षा योग्यता की आवृत्ति 31 है और प्रतिशत 25.8 है। स्नातकोत्तर और उससे ऊपर की शिक्षा योग्यता की आवृत्ति 86 है और प्रतिशत 71.7 है। डिप्लोमा में शिक्षा योग्यता की आवृत्ति 2 है और प्रतिशत 1.7 है
- अन्य में शिक्षा योग्यता की आवृत्ति 1 है और प्रतिशत व्याख्या है: शैक्षिक क्षेत्र में अधिकांश महिलाएँ स्नातकोत्तर थीं।

तालिका 5.3 धर्म की आवृत्ति

		आवृत्ति	प्रतिशत	वैध प्रतिशत	संचयी प्रतिशत
वैध	हिंदू	74	61.7	61.7	61.7
	मुस्लिम	3	2.5	2.5	64.2
	ईसाई	42	35.0	35.0	99.2
	अन्य	1	.8	.8	100.0
	कुल	120	100.0	100.0	

- हिंदुओं की आवृत्ति 74 है और प्रतिशत 61.7 है। मुसलमानों की आवृत्ति 3 है और प्रतिशत 2.5 है। ईसाइयों की आवृत्ति 42 है और प्रतिशत 35 है।
- **व्याख्या:** शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है।

तालिका 5.4: प्रतिगमन परिणाम – ऐसे तत्व हैं जो समग्र वित्तीय स्तर को संचालित करते हैं।

आश्रित चर: समग्र वित्तीय कारक	अमानकीकृत गुणांक		मानकीकृत गुणांक		
स्वतंत्र वित्तीय चर नीचे दिए गए हैं	बीटा	मानक त्रुटि	बीटा	t	Sig.
(स्थिर)	0.012	0.006		2.065	0.039
आय (C1)	0.032	0.002	0.235	18.206	0.000
घरेलू व्यय (C2)	0.020	0.002	0.144	12.262	0.000
घरेलू टिकाऊ वस्तुओं पर व्यय (C3)	0.021	0.001	0.175	14.358	0.000
स्वास्थ्य देखभाल व्यय पर बचत करने की क्षमता (C4)	0.021	0.001	0.192	15.073	0.000
शैक्षणिक व्यय पर बचत करने की क्षमता (C5)	0.019	0.001	0.178	13.921	0.000
स्थायी परिसंपत्तियों पर निवेश करने की क्षमता (C6)	0.020	0.002	0.185	10.483	0.000
गैर-स्थायी परिसंपत्तियों पर निवेश (C7)	0.020	0.002	0.194	10.978	0.000

मॉडल का समीकरण: समग्र वित्तीय स्तर = $0.012 + 0.032'C_1 + 0.020'C_2 + 0.021'C_3 + 0.021'C_4 + 0.019'C_5 + 0.020'C_6 + 0.020'C_7$

व्याख्या: शून्य परिकल्पना जो कहती है कि महिला उद्यमियों के लिए समग्र वित्तीय सशक्तिकरण भागफल और अन्य वित्तीय कारकों के बीच कोई संबंध नहीं है, को अस्वीकार कर दिया गया है।

वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है क्योंकि शिक्षा और कृषि के संयुक्त क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए सशक्तिकरण भागफल के बीच समग्र वित्तीय कारकों और ऊपर उल्लिखित अन्य वित्तीय कारकों के संबंध में सकारात्मक सहसंबंध है। सशक्तिकरण भागफल के पाँच कारकों में से, वह कारक जिसका समग्र वित्तीय कारकों पर अधिकतम प्रभाव पड़ता है, वे हैं (C1), (C3) और (C4)।

तालिका 5.5: समग्र मानव कारक और मानव कारक के तत्वों के बीच विचरण के विश्लेषण का परिणाम

फिट की अच्छाई के आँकड़े:		विचरण का विश्लेषण:					
			वर्गों का योग	df	माध्य वर्ग	F	Sig.
अवलोकन	500.000	प्रतिगमन	5.142	9	0.571	632.808	.000
भार का योग	500.000	अवशिष्ट	0.443	491	0.001		
DF	491	कुल	5.585	500			
R ²	0.921						
समायोजित R ²	0.919						
DW	1.815						

तालिका 5.6: प्रतिगमन परिणाम – ऐसे तत्व हैं जो समग्र मानव कारक को संचालित करते हैं।

आश्रित चर: समग्र मानवीय कारक	अमानकीकृत गुणांक		मानकीकृत गुणांक		
स्वतंत्र मानवीय चर इस प्रकार हैं	बीटा	मानक त्रुटि	बीटा	t	Sig.
(स्थिर)	0.061	0.007		8.470	0.000

जीवन में मूल्यों का सकारात्मक परिवर्तन (D1)	0.007	0.002	0.075	3.875	0.000
जीवन में मूल्यों का सकारात्मक परिवर्तन (D2)	0.028	0.002	0.274	12.854	0.000
बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य में सुधार (D3)	0.011	0.002	0.121	6.558	0.000
परिवार के अन्य सदस्यों की तरह पौष्टिक भोजन का सेवन (D4)	0.018	0.002	0.196	10.005	0.000
मानव कौशल में सुधार (D5)	0.015	0.002	0.170	9.186	0.000
घर और व्यवसाय में संतुष्टि के लिए संतुलन (D6)	0.011	0.002	0.107	5.634	0.000
घर-जीवन संतुलन ने पारंपरिक रूप से परिवार में बंधे रहने में सक्षम बनाया है (D7)	0.012	0.002	0.108	5.709	0.000
परिवार में सम्मान प्राप्त होना (D8)	0.019	0.002	0.203	8.192	0.000
परिवार के सहयोग से संतुष्ट होना (D9)	0.012	0.002	0.128	5.302	0.000

मॉडल का समीकरण: समग्र मानव कारक = $0.061 + 0.007'D_1 + 0.028'D_2 + 0.011'D_3 + 0.018'D_4 + 0.015'D_5 + 0.011'D_6 + 0.012'D_7 + 0.019'D_8 + 0.012'D_9$

व्याख्या:

शून्य परिकल्पना जो कहती है कि महिला उद्यमियों के लिए समग्र मानव सशक्तिकरण भागफल और अन्य मानवीय कारकों के बीच कोई संबंध नहीं है, को खारिज कर दिया गया है।

वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है क्योंकि शिक्षा और कृषि के संयुक्त क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए सशक्तिकरण भागफल के बीच समग्र मानव कारकों और ऊपर वर्णित अन्य मानवीय कारकों के संबंध में सकारात्मक सहसंबंध है। सशक्तिकरण भागफल के पांच कारकों में से, वह कारक जिसका समग्र मानव कारकों पर अधिकतम प्रभाव पड़ता है, वे हैं (D2) और (D8)।

6. निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आज एक ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है जहाँ महिलाएँ अपने व्यक्तिगत विकास पर स्वतंत्र निर्णय ले सकें और साथ ही समाज में बराबरी की स्थिति में आ सकें। गरीबी को दुनिया में शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है और अशिक्षा के उन्मूलन के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन भी राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए। गरीबी के कारण महिलाओं का शोषण होता है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत में महिला सशक्तिकरण आज के समय का ज्वलंत विषय है।

महिला सशक्तिकरण क्या है, इसे सही मायने में समझने के लिए सरकार की ओर से वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता और अन्य प्रौद्योगिकी संचालित कार्यक्रमों की योजनाएँ लानी होंगी।

दूसरी ओर, यह देखा गया है कि भारत की दो-तिहाई आबादी राष्ट्रीय औसत आयु 26 वर्ष से कम है, जिसका अर्थ है कि आने वाले दशक में देश में संभावित कार्यबल एक अरब को छू जाएगा। रोजगार दरों को स्थिर रखने के लिए अर्थव्यवस्था को हर महीने 5 मिलियन नौकरियाँ सृजित करने की आवश्यकता होगी। सृजित की जाने वाली लगभग 90 प्रतिशत नौकरियाँ कौशल आधारित होंगी और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को सशक्त बनाना रोजगार के संबंध में सरकार की नीतियों को पूरा करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि रोजगार की सबसे अधिक संभावना बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आतिथ्य और सुविधा प्रबंधन, खुदरा, निर्माण और सूक्ष्म उद्यम में है। वर्तमान सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि भारत के सभी युवाओं को अपना खुद का उद्यम शुरू करने में रुचि होनी चाहिए। इस संबंध में, सरकार ने स्टार्टअप इंडिया नामक एक योजना शुरू की है। यह एक ऐसा फ्लैगशिप बनाने के इरादे से स्थापित किया गया है जो युवाओं के अभिनव विचारों के पोषण के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम का निर्माण कर सके। ये स्टार्टअप देश के आर्थिक विकास पर काम करेंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- मॉटेक एस. अहलूवालिया (1990) गरीबी उन्मूलन के लिए नीतियाँ समीक्षा: एशियाई और प्रशांत आर्थिक मुद्दों का अध्ययन; खंड 8, संख्या 1, पृष्ठ 3.
- माइक्रोक्रेडिट के साथ गरीबी से लड़ना: -123 से अनुभव।
- माइक्रोफाइनेंस क्रांति गरीबों के लिए सतत वित्त डी.सी.: पीपी ग्टप्प, 304,
- सिमानोविट्ज, ए. (2001), गरीबों के लिए माइक्रोफाइनेंस: इम्प-एक्ट के योगदान के लिए मुद्दों और विचारों की समीक्षा, इम्प-एक्ट कंसोर्टियम, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, ब्राइटन, यूके।

- भारत में गरीबी की पुस्तिका: परिप्रेक्ष्य, नीतियां और कार्यक्रम ", ऑक्सफोर यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली 9.122.
- अबू एन.एम. वाहिद (1974) द ग्रामीन बैंक एंड पॉवर्टी एलिमिनेशन इन बांग्लादेश: थ्योरी, एविडेंस एंड लिमिटेशंस, "अमेरिकन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी वॉल्यूम.53, नंबर 1, , पी.2.
- बैंक फॉर द डाउन एंड आउट सितंबर पीपी 16–18.
- एडम्स, डी.डब्ल्यू.; और वोगेल, आर.सी. —इनकम वर्ल्ड डेवलपमेंट, वॉल्यूम. 14, पीपी. 477–88.
- इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम. 40, नंबर 17, पी. 1733.
- अमर्त्य विकास स्वतंत्रता के रूप में पृष्ठ 39.
- आर्थिक विकास पियर्सन शिक्षा, नई दिल्ली, खंड 1, पृष्ठ 111–114
- बांग्लादेश में गरीब परिवारों पर समूह-आधारित ऋण कार्यक्रमों का प्रभाव: क्या प्रतिभागियों का लिंग –996.
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण गरीबी में कमी इंडियन जर्नल ऑफ मेड रेस 126, पृष्ठ 381–389.
- सुधार के बाद की अवधि के दौरान केरल में गरीबी की सीमा और तीव्रता; धारावाहिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ 215 से 243.
- बीपीएल जनगणना 2009 के लिए कार्यप्रणाली पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट
- गरीबी के खिलाफ वित्त प्रकाशन, लंदन, खंड प्, पृष्ठ 123
- मोस्ले पी (2001), माइक्रोफाइनेंस और गरीबी बोलिविया: जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, खंड 37, संख्या 4, पृष्ठ 101–32।
- माइक्रोक्रेडिट कार्यक्रम कौन भाग लेता है और किस हद तक ठाढ़-पक्वत्त, वर्किंग पेपर संख्या 12, संयुक्त अनुसंधान परियोजना, ढाका, बांग्लादेश, पृष्ठ 124
- घाटे, पी. (2007), भारत में माइक्रोफाइनेंस: सेक्टर की स्थिति रिपोर्ट, 2006, माइक्रोफाइनेंस इंडिया प्रकाशन, नई दिल्ली।
- घाटे, पी. (2008), भारत में माइक्रोफाइनेंस: सेक्टर की स्थिति रिपोर्ट, 2007, माइक्रोफाइनेंस इंडिया प्रकाशन, नई दिल्ली।
- हुल्मे, डी.; और मोस्ले, पी. (1996), गरीबी के खिलाफ वित्त, रूटलेज, लंदन।
- आईआईएमएस (2007), "समावेशी वित्तीय प्रणाली की ओर: भारत के कानून आय कार्यबल द्वारा वित्तीय सेवा की मांग और उपयोग"। डेटावर्क रिसर्च रिपोर्ट, इन्वेस्ट इंडिया मार्केट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।